भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 102

सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक)

गोवा के परंपरागत व्यवसाय

102. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गोवा के बढ़ईगीरी, राजमिस्त्री और बुनकर जैसे स्थानीय व्यवसायों में प्रवासी श्रमिकों की अधिकता को देखते हुए राज्य और केन्द्र सरकार दोनों ही इन व्यवसायों में गोवा के युवाओं को संलग्न रखने के लिए प्रशिक्षुता योजनाओं या व्यावसायिक केन्द्रों में निवेश करने में विफल रही हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) तटीय मत्स्यपालन नियमों को लागू करने तथा अनियमित पुराने ट्रॉलरों और पर्यावरणीय क्षरण के कारण पीड़ित पारंपरिक मछली पकड़ने वाले समुदायों को नई पेट्रोल-नौकाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा की गई ठोस कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार शहरी सीमांतीकरण और राज्य के सहयोग की कमी के कारण मिट्टी के बर्तन, बेंत की बुनाई जैसे स्थानीय शिल्पों के विलुप्त होने को देखते हुए सांस्कृतिक संपत्तियों को बनाए रखने के लिए लक्षित वित्त-पोषण, बाजार संपर्क और जागरूकता अभियान शुरू करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार गोवा की पाक परंपराओं और परिवारों द्वारा संचालित बेकरियों के पतन के मद्देनजर, व्यावसायिक बदलावों के प्रति संवेदनशील हस्तशिल्प खाद्य व्यापारों के लिए विरासती अनुदान, तकनीकी आधुनिकीकरण सहायता और विरासती प्रमाणन शुरू करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) भारतीय युवाओं को कार्यस्थल पर प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने हेतु भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा मुंबई, कानपुर, चेन्नई और कोलकाता स्थित चार क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्डों (बीओएटी/बीओपीटी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

एनएटीएस नए स्नातकों, डिप्लोमा धारकों और डिग्री प्राप्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करता है। स्नातक/डिग्री प्रशिक्षुओं के लिए निर्धारित न्यूनतम छात्रवृत्ति 9,000 रुपये प्रति माह और तकनीशियन/डिप्लोमा प्रशिक्षुओं के लिए 8,000 रुपये प्रति माह है। भारत सरकार प्रशिक्षुओं के लिए निर्धारित न्यूनतम छात्रवृत्ति का 50% प्रदान करती है। एनएटीएस द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में क्रमशः 1.48 लाख, 2.68 लाख और 2.57 लाख प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया है।

जारी -2/-

सरकार ने छात्रों, उद्योग और उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को एकल मंच पर लाने के लिए एनएटीएस 2.0 पोर्टल की शुरु किया है । एनएटीएस 2.0 पोर्टल के माध्यम से, सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से छात्रवृत्ति के अपने हिस्से का संवितरण शुरू कर दिया है।

एनएटीएस के अंतर्गत नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रशिक्षुता मेलों, करियर मार्गदर्शन कार्यक्रमों और उद्योग-संस्थान बैठकों के रूप में कई आउटरीच गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं। इसके अलावा, एनएटीएस की पहुँच को बेहतर बनाने के लिए, सीएससी नेटवर्क का लाभ उठाने हेतु सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

गोवा राज्य में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान नियोजित प्रशिक्षुओं और योजना के अंतर्गत पंजीकृत उद्योगों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	कुल नियोजित प्रशिक्षु	अब तक कुल पंजीकृत उद्योग
2021-22	529	118
2022-23	766	123
2023-24	798	137

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना दिनांक 17.09.2023 को शुरू की गई थी ताकि बढ़ई, राजमिस्त्री सहित 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान की जा सके, जो अपने हाथों और औज़ारों से काम करते हैं। इस योजना के तहत, गोवा सहित देश भर के प्रधानमंत्री विश्वकर्मा लाभार्थियों को मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, कौशल उन्नयन आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को विभिन्न व्यापार मेलों, राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से अपने हस्तशिल्प/उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को ऑनलाइन मार्केटिंग सहायता भी प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत, गोवा सहित देश भर के लाभार्थियों को मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता से लेकर प्रौद्योगिकी, पोस्ट हार्वेस्टिंग बुनियादी ढांचे और मार्केटिंग आदि तक मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।इस योजना का उद्देश्य मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करना, पता लगाने की क्षमता को बढ़ाना और एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा स्थापित करना है, साथ ही मछुआरों और मछली उत्पादन करने वालों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना है।

*****